जनगर्जन

वर्ष 25 अंक 3 मासिक नई दिल्ली नवम्बर-2010 विक्रमी संवत्-2067 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक-शुल्क: 60रुपये

भ्रष्टाचार राज के पर्दाफाश के लिये गहरी जाँच जरूरी

देवब्रत बिश्वास, महासचिव, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक

कांग्रेस नीत संप्रग-2 सरकार एक के बाद एक घोटालों से ग्रसित होती जा रही है जिसे भ्रष्टाचार राज कहा जा सकता हैं। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुये कॉमन वेल्थ गेम्स (राष्ट्रकुल खेल) 2010 में देश को भारी शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भारत की छवि को धक्का लगा है। उक्त खेल से जुड़े अप्रत्याशित घाटालों जिसमें 70,000 करोड़ रुपये की अनियमितता जुड़ी हुई है सामने आई और सांगठनिक कमिटी के नेता कांग्रेस के सांसद सुरेश कल्माड़ी थे। इसमें सबसे अधिक कष्टदायक बात यह है कि इतने भयानक भ्रष्टाचार के जुड़े प्रसंग के बावजूद केन्द्रीय मंत्रीमण्डल मूक दर्शक बना रहा और भ्रष्ट सांगठनिक कमिटी को इस तथ्य के उजागर होने के बाद कार्य करते रहने दिया। अब सरकार बहुत नरम तरीके से उक्त संदर्भ में हुई अनियमितताओं (जैसा केन्द्रीय खेल मंत्री एम.एस. गिल ने कहा था) की जाँच के लिये सामने आई है जबकि सुरेश कल्माड़ी को दिखावे के तौर पर संसदीय कमिटी के पद से हटा दिया गया है जिसका जनता के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा।

वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी मुम्बई के महँगे फ्लैटों के अवैध आबंटन के घोटाले में डूबे पाये गये और इस तरह जनता और अधिक कांग्रेसियों के द्वारा फैलाये भ्रष्टाचार के उजागर से उत्तेजित हो गयी है। ये फ्लैट कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों व उनके अन्य आश्रित परिवार जनों के लिये कम कीमत पर बनाये गये थे। जब यह भ्रष्टाचार जगजाहिर हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व ने जनता के आवेग को शांत करने के लिये अशोक चव्हाण को हटाकर पृथ्वी राज चव्हाण जो प्रधानमंत्री के काफी नजदीकी माने जाते है, को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त किया।

संप्रग-2 सरकार के छवि को बचाने का जो प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे है वह असफल होगा। एक समय विदेश राज्य मंत्री शशी थरूर को आईपीएल खेलों के घोटालों में जुड़ा पाये जाने पर प्रधानमंत्री ने मंत्री मण्डल से उन्हें हटाकर अपने स्वस्छ छवि का जो दावा किया था वह असफल रहा। अंतत: मनमोहन सिंह अपने सरकार की साफ और भ्रष्टाचार मुक्त छवि को नहीं बचा सके। विपक्षी दल एक लम्बे समय से केन्द्रीय संचार मंत्री ए. राजा के 2 जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के प्रकरण में बरते जा रहे गलत रवैये की शिकायत किया था जिसमें इन्हें मंत्रिमण्डल से हटाने का अनुरोध किया था। परन्तु इस प्रकरण में प्रधानमंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं कि और ए. राजा के क्रियाकलापों का समर्थन भी किया, जिसका नतीजा एक अप्रत्याशित भयानक घोटाले के रूप में सामने आया जो किसी भी तरह छुपाये न छुपा और सीएजी की 2-जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के ऊपर प्रस्तुत रिपोर्ट में खुल के सामने आया।

सीएजी महोदय की रिपोर्ट में (संख्या 19, 2010-11) के अनुसार "इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता का अभाव था और निर्णय निरंकुश, गलत और अनुचित तरीके से लिये गये थे", जिसमें सरकारी खजाने से 1 करोड़ 76 लाख करोड़ की अनुमानित क्षति दर्शायी गयी। यह दर्शायी गयी राशि एक अनुमान मात्र है। जिसे किसी भी तरह हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह तथ्य अत्यंत अधिकारिक सूत्र सीएजी के द्वारा सामने लाया गया है जिसने अत्यंत सूक्ष्मता से इस भ्रष्टाचार के हर पहलू पर ध्यान दिया है। इसके हर ब्यौरे पर टिप्पणी की है। देखने से इस घोटाले ने सभी घोटालों को बौना साबित कर दिया है। बोफोर्स घोटाला जो एक समय चर्चा में था वह 67 करोड़ रुपये का था जिसके सामने यह घोटाला कई गुणा बड़ा है। इस घोटाले का गंभीर पक्ष यह है कि मंत्री ए. राजा को इस्तीफा देने के लिये भारी दबाव बनाना पड़ा है क्योंकि वे लगातार अपने कार्य को नियमानुसार चलाने तथा प्रधानमंत्री के संज्ञान और स्वीकृति की दुहाई दे रहे थे और प्रधानमंत्री स्वयं भी ए. राजा के दावों का विरोध करते हुये नहीं दिख रहे थे और इस तरह संप्रग द्वितीय सरकार के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने का तथ्य सामने आया।

यह प्रकरण और अधिक चिंताजनक बन गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री को इससे जुड़े प्रकरण में 16 महीने से चुप्पी साधने के कारण को पूछा। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा।

संसद के शीतकालीन सत्र में पूरा विपक्ष इस 2-जी स्पेक्ट्रम के आबंटन प्रकरण में घोटाले में हुये जाँच के लिये संयुक्त संसदीय कमिटी (जेपीसी)

की मांग कर रहा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे राष्ट्र और संसद की भावना को दरकिनार कर सरकार इसे अनदेखा कर रही है। विपक्ष की इस मांग को न मानने से संसद की कार्यवाही स्थगित चल रही है।

प्रधानमंत्री की निष्क्रियता को कुछ लोग उन्हें गठजोड़ की मजबूरी की संज्ञा दे रहे है क्योंकि सरकार के अस्तित्व की रक्षा के लिये डीएमके सहयोग की जरूरत है। ऐसा ही मामला गठजोड़ के एक भागीदार तृणमूल कांग्रेस का भी है जिसकी नेत्रि केन्द्रीय रेल मंत्री है जो पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों की माओवादी हिंसा से प्रभावित है में उनके ऊपर नकेल कसने के लिये केन्द्र सरकार के केन्द्रीय बलों को भेजें जाने के निर्णय का विरोध कर रही है और रूकावट बनकर खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस केन्द्र सरकार के इस कदम सार्वजनिक रूप से आलोचना भी करती है वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में वाम दलों की सरकार के विरुद्ध चुनावी लाभ लेने के लिये माओवादियों के साथ खड़ी दिखती है। इस पूरे प्रकरण पर वाम दलों के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री और संप्रग सरकार चुप्पी साधे हुये है। इसका सीधा अर्थ है कि तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से केन्द्र में सरकार चलाते रहा जाये इस तरह देश में अनैतिक तरीके से भारी भ्रष्टाचार फैलाकर भ्रष्टाचार राज कायम करने का कार्य कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है।

भ्रष्टाचार राज के खिलाफ संघर्ष करते समय जनता को अपने लक्ष्य की पहचान सजगता पूर्वक करनी चाहिये। केन्द्र में वर्तमान प्रमुख विपक्षी दल भाजपा भी भ्रष्टाचार के इस क्रमवार प्रकरण पर अत्यंत मुखरित दिख रही है जबकि वह खुद कर्नाटक राज्य में जहाँ उसकी सरकार है एक बड़े जमीन घोटाले में फंसी दिख रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने दोहने मानदण्ड अपनाते हुये अपने सगे-संबंधियो को जमीन आबंटन के भ्रष्टाचार में पकड़े गये है। इधर कुछ वर्षों से जिसमें उनके दो पुत्र, पुत्री और बहन को भारी कीमती भूमि-भवन बेंगलौर के आस-पास दिये गये है जिन्हें प्रारंभ में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिये सरकार ने अधिग्रहित किया था तथा साथ में अवैध खनन के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार का मामला भी है।

यह भ्रष्टाचार राज देश में पूरे-शोर से जारी है। जनता का संयुक्त संघर्ष जो वामशक्तियों के नेतृत्व में हो की इस भ्रष्टाचार राज के खात्मे के लिये जरूरत है। इस तरफ एक कदम के रूप में होता यदि 2-जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले की जाँच संयुक्त संसदीय समिति ही गंभीरता पूर्वक करें।

सु की आजाद हुई : लोकतंत्र अभी भी बहुत दूर

1989 के बाद कई यातनायें सहते हुये पन्द्रह वर्षों तक कैद और नजरबंद रहते हुये म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक महान नेत्रि आंग सान सू की अंततः आजाद हुई। मिलिट्री जुनता के द्वारा उन्हें दी गयी आजादी का स्वागत म्यांमार की जनता ने अपने हृदय से किया। परंतु जनता अभी भी भयाक्रांत है कि उन्हें कहीं दुबारा गिरफ्तार न कर लिया जाये जैसा कि वहाँ पहले भी हुआ है और लोकतंत्र की आवाज को दबाया गया हैं। जुनता ने हाल ही में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को सबसे बड़े लोकप्रिय दल के रूप में मान्यता दी है जिसे सू कि का नेतृत्व प्राप्त है। गत वर्ष 7 नवम्बर को संपन्न हुये आम चुनाव में उन्हें भाग लेने की स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि उसका आयोजन सैनिक प्रशासन ने किया और अधिकांश सीटों पर जुनता समर्थित उम्मीदवार विजयी हुये थे। प्रकट रूप से अब यह देखना है कि जुनता सत्ता का हस्तांतरण नागरिक सरकार को पिछले वर्ष संपन्न हुये छलावे युक्त आम चुनाव के बाद करती है कि। इस तरह लोकतंत्र अभी वहाँ काफी दूर है। याद रहना चाहिये कि देश में स्वतंत्र रूप से संपन्न हुये 1990 के चुनाव में एनएलडी ने भारी सफलता प्राप्त की थी परंतु उन्हें नागरिक सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी गयी। फिर भी साहस की प्रतिमूर्ति सू की अविचलित रही और सैनिक जुनता के देश व्यापि दमन के विरुद्ध छेड़े लोकतांत्रिक संघर्ष को बनाये रखी। हजारों लोग जेल में डाले गये और तरह-तरह की यातनायें सहते रहे। 65 वर्षीय सू की ने आजाद होने के बाद जनता को जारी संदेश में कहा कि सही मायने में लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिये लोगों को एक साथ संयुक्त रूप से कार्य करना होगा।

हम उम्मीद करते है कि सू की के प्रेरणा दायक नेतृत्व में अंततः म्यांमार में लोकतंत्र आयेगा। इसी उम्मीद से जैसा कि याद करना चाहिये वर्ष 2007 के आरम्भ में ही नेताजी सुभाष फाउण्डेशन ने उन्हें बधाई दिया था जब वे म्यांमार में नजरबंद थी और फाउण्डेशन ने अपनी तरफ से उन्हें नेता सुभाष चन्द्र बोस पुरस्कार 2007 से अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा था। यह पुरस्कार उनके दल के भारत स्थित प्रतिनिधि ने 19 मार्च 2007 को महाजाति सदन, कोलकाता में स्वीकार किया था। यह पुरस्कार देते समय फाउण्डेशन ने अपने प्रपत्र में कहा था "दमन की बेड़ियों ने आपके आँखों में जल रही अग्नि को मध्यम नहीं किया, घोर निराशा में भी आप उम्मीद की कीरण बनकर उपस्थित है, साहस, सम्मान और दृढ़ता की आप प्रतिमूर्ति है, हम उम्मीद करते है कि आप अपने जीवनकाल में ही अपनी मातृभूमि को इच्छानुसार मुक्त कराने में सफल होंगी, विजय आपके साथ होगी।"

इस विजय में पहला कदम हो चुका है। 'भारत-बर्मा पिपुल्स' मित्रता को याद करते हुये व्यतीत ब्रिटिश काल में नेताजी के साथ साम्राज्यवाद के संयुक्त संघर्ष में और बर्मा की धरती पर भारत की आजादी के लिये 'दिल्ली चलो' के आजाद हिन्द फौज की मजबूत उपस्थिति इस बात की गवाही देती है कि हम एकबार पुनः निरंकुश दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट हो जाये। भारत की मुक्तिकामि जनता की तरफ से हम सभी लोग म्यांमार की जनता के प्रति समर्थन व्यक्त करते है जो अपने क्रांतिकारी नेत्रि आन सांग सू की के नेतृत्व में लोकतंत्र की स्थापना के लिये कड़ा संघर्ष कर रहे हैं।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार पिछले कई वर्षों से इस जुनता सरकार के सौहार्द्धपूर्ण व्यवहार बनाये हुये है। इसी तरह अन्य पड़ोसी देश जैसे चीन और बांग्लादेश जुनता सरकार के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग बनाये हुये है। उनके बयान अपने देशों के व्यवसायिक लाभ पर आधारित है जहाँ

व्यवसायिक लाभ अधिक महत्त्वपूर्ण है और वैचारिक प्रेरणात्मक लोकतंत्र की म्यांमार में स्थापना गौण है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है हम एक विशालतम लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते है और ऐसा व्यवहार म्यांमार के प्रति करते है जो निंदनीय है। आश्चर्य की बात है कि अन्य साम्राज्यवादी देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन हमेशा से म्यांमार की जुनता प्रशासन का विरोध करते रहे है। यहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने अपने व्यांगात्मक लहजे में हाल में संपन्न हुये अपनी भारत यात्रा में कहा कि 'जहाँ म्यांमार में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है और दमन सरकारी नीति बन चुका है, भारत म्यांमार के प्रकरण पर मौन क्यों है'। ऐसी आलोचना उचित है, परन्तु ऐसा प्रश्न कम से कम अमेरिका कैसे उठा सकता है, जो इसी तरीके के अपराध फिलिस्तिन, इराक, अफगानिस्तान व अन्य जगहों पर कर रहा है।

ऐसे ही विवादास्पद मौके पर म्यांमार की जनता सरकार ने सू की को रिहा किया है उसे ऐसा लगता है कि आम चुनाव तो एक वर्ष पहले हो चुके है जिसमें सू कि की पार्टी प्रतिबंधित थी और पूरी तरीके से बाहर चुकी है तथा वहीं प्रतिक्रिया वादी जुनता समर्थक उम्मीदवार जीतकर अच्छी संख्या में आ चुके है तो एनएलडी नेत्रि धीरे-धीरे म्यांमार में अप्रासंगिक होकर अपनी छवि को धूमिल करती जायेंगी। जुनता यह भी उम्मीद करती है कि उनको रिहा करने से एक लोकतंत्र समर्थक नेता की रिहाई हुई है जिससे पश्चिम के महत्त्वपूर्ण देशों के साथ उनके आर्थिक रिश्ते बहाल हो जायेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आर्थिक प्रतिबंधों को म्यांमार के लिये बन्द कर देगा और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसे और अधिक संपर्क मिलेंगे।

लेकिन यह सभी आकलन और उम्मीदें सत्य नहीं भी सिद्ध हो सकती है। आज भी हजारों राजनैतिक कैदी जुनता के शासनकाल में जेलों में पड़े हुये है और किसी भी तरह से लोकतंत्र को विकसित करने का उचित माहौल नहीं है। पिछले दो दशकों में जो भी चुनौतियों सू की ने झेली है उनमें अब सामने आई चुनौतियाँ अधिक बलशाली है। परन्तु अपने लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति समझौता करने का अपार साहस है। हम उम्मीद करते है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र को बल प्रदान करने के प्रेरणा स्वरूप वे म्यांमार में अपने राजनैतिक कार्य करेंगे।

हम सभी क्रांतिकारी लोकतंत्र नेत्रि आन सांग सू की की रिहाई का स्वागत करते हैं।

अमेरिकी सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन

नई दिल्ली : 8 नवम्बर 2010 अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा भारत दौरे के दौरान जब संसद की दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे थे तब भारत की चारों वामपंथी पार्टियों - सीपीएम, सीपीआई, फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी, के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग पर अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान वामपंथी पार्टियों द्वारा राष्ट्रीय स्पर पर विरोध प्रदर्शन करने के आह्वान के तहत दिल्ली राज्य कमिटियों द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने में सम्मिलित थे साथी ए.बी वर्द्धन, महासचिव सीपीआई, साथी प्रकाश करात, महासचिव सीपीएम, साथी देवब्रत बिश्वास, महासचिव फारवर्ड ब्लॉक, साथी अबनी राय, सचिव आरएसपी, साथी अमरजीत कौर व दिनेश वाष्णेय, सीपीआई, पुष्पिंदर ग्रेवाल व विजेन्द्र शर्मा, सीपीएम, धर्मेन्द्र वर्मा - फारवर्ड ब्लॉक, और असित गांगुली - आर.एस.पी.।

प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर इकट्ठा होकर संसद की ओर मार्च किया जहाँ पुलिस ने बेरीकेड पर उन्हें रोका। प्रदर्शनकारी भोपाल गैस काण्ड के आरोपी वारेन एण्डर्सन को भारत को सौंपने, दऊ कैमिकल कम्पनी द्वारा कैमिकल वेस्ट कोसाफ करने की जिम्मेदारी लेने, इराक व अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजे वापिस करने, फिलिस्तिन व अरब देशों के इलाकों को खाली न कर रहे इजरायल को अमेरिकी समर्थन बंद करने आदि के नारे लगे रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अमेरिकी प्रशासन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित में भारत पर शिक्षा, कृषि व खुदरा व्यापार में विदेशी पूँजी लगाने के अपने दबाव को बंद करे तथा भारत सरकार इस दबाव के आगे देश के हितों के मद्देनजर घुटने नहीं टेके। उनकी मांग थी कि बाराक ओबामा प्रशासन क्यूबा के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी वापिस ले।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुये वक्ताओं ने कहा कि अमेरिका के मिलिट्री औद्योगिक संस्थानों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की रक्षा में भारत अपने देश के हितों को कुर्बान नहीं करे बल्कि इण्डो - यू.एस. स्ट्रेटेजिक समझौता रद्द करे।

उनका कहना था कि हेडली जो अमेरिका का डबल एजेंट का काम कर रहा था, द्वारा दी गयी जानकारी भारत को समय रहते नही दी गई और 26 नवंबर को आतंकी हमला हो गया। इसके बाद भारत यह क्यों यकीन करे कि अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर होकर मदद करेगा। असलियत तो यह है कि अमेरिकी प्रशासन दुनिया में अपने मिलिट्री व आर्थिक वर्चस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत को स्ट्रैटेजिक सहयोगी बनाना चाह रहा है।

उन्होंने मांग की कि भारत को अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून को सप्लायर कम्पनियों के हितों में संशोधित करने के दबाव को अस्वीकार करे।

अखिल फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की बैठक का प्रस्ताव

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की केन्द्रीय कमिटी की बैठक दिनांक 4 और 5 नवम्बर 2010 को नई दिल्ली में हुई। जिसमें देश की वर्तमान राजनीतिक और पार्टी की जन संगठनों की राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई तथा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

ओबामा का भारत दौरा

अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बाराक ओबामा का 6 से 9 नवम्बर तक भारत का दौरा किया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने इस पर समीक्षा किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि पार्टी का मत है कि अमेरिका में सत्ता के परिवर्तन से तीसरी दुनिया के देशों के प्रति अमेरिकी विचारों में कोई परिर्वतन नहीं हुआ है। फिलिस्तिन, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा और अन्य लैतिन अमेरिकन देशों के प्रति अमेरिकी का आक्रामक नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। श्रीमान ओबामा से दुनिया को जो उम्मीदें थी उस पर वे खरे नहीं उतरे और भविष्य में कोई बदलाव के संकेत दिखाई नहीं देते है।

ओबामा का भारत भ्रमण का मुख्य लक्ष्य अपनी नीतियों को साकार करना तथा भारत और अमेरिका के बीच सैनिक गठबंधन बढ़ाना, भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति में बदलाव बनाना है – यह भारत की संप्रभुता के लिये गंभीर खतरा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिकी प्रशासन अमेरिकी की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को तरोताजा बनाने के लिये भारतीय निवेश को आकर्षित करेगा।

भारत सरकार ने पहले ही अमेरिकी कम्पनियों को 12 अरब डॉलर का व्यापारिक समझौता का वादा कर चुकी है, जिसमें से 5 अरब डॉलर हथियारों की खरीद–फरोख्त है तथा शेष वाणिज्यिक सौदे। एक अनुसार के अनुसार भारत के इस 12 अरब डॉलर के समझौते से प्रत्यक्ष रूप से 60,000 अमेरिकी लोगों को नौकरी मिलेगी। अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी कृषि उत्पाद को अमेरिका से आयात करने के लिय एक सरल और आसान रास्ता बनाना ही ओबामा का भारत दौरे का लक्ष्य है। भारतीय किसान, जो पहले ही से सरकार की किसान विरोधी नीति से पीड़ित है, उनका गला घोटने का एक और नया कदम होगा। अमेरिका अपने किसानों को कई तरह से विभिन्न सब्सिडि देता है, जबकि भारत भी मामूली सी सब्सिडी देता है लेकिन यह सब्सिडी दिखावा मात्र है। यह मुद्दा विश्व व्यापार समझौते की दोहा राउण्ड की वार्ता से लगातार इन दोनों देशों के मध्य वार्ता का मुख्य विषय रहा है।

नौजवान भारतीय को यह नहीं भूलना चाहिये कि श्रीमान ओबामा ने अमेरिकी आधारित भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों पर घटिया तरीकों से बाहरी स्रोतों को ठेके पर देने की बात कही थी। उनके इस कार्यकाल में अमेरिकी आधारित कम्पनियों को मुनाफा दिलाने के लिये कई बातों का उदय हुआ है कि जिसमें – कर की उच्च दर, सब्सिडी में कटौती, लाईसेंस फीस में बढ़ोतरी आदि शामिल है। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्होंने बेंगलौर, कोलकाता और हैदराबाद स्थित 'आई हब' का दौरा नहीं किया।

इसके अलावा श्रीमान ओबामा के शासन काल के दौरान अमेरिकी प्रशासन ने निपुण कारिगरों के लिये वीजा फीस में भी बढ़ोतरी करते हुये वीजा फीस 320 डॉलर से बढ़ाकर 570 डॉलर कर दिया। जिससे भारतीय निवेशक अमेरिकी लोगों को ही रोजगार पर रखें। यह गौरतलब हो कि अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारतीय कम्पनियाँ दूसरे नंबर पर सबसे बड़े निवेशक है, जो 57000 नये अमेरिकियों को नौकरी मुहैया करायेगा।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, इन सभी कारणों से श्रीमान बाराक ओबामा के भारत दौरे का विरोध करता है। हम लोग अमेरिकी जनता के विरोधी नहीं है और न ही हम अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा का अनादर कर रहे है, बल्कि हमारा विरोध तीसरी दुनिया के देशों की की जनता के प्रति आक्रामक अमेरिकी नीतियों का विरोध है। पार्टी इन इस संदर्भ में 6 से 12 नवम्बर 2010 तक राष्ट्रव्यापि साप्ताहिक आन्दोलन किया। ओबामा के भारत दौरे का विरोध करने के लिये लोगों को गली–मोहल्लों में जाकर पार्टी तथा जन संगठनों ने समाज के हर वर्ग व क्षेत्र को संदेश दिया। 8 नवम्बर 2010 को जब संसद के दोनों सदनों को अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा संबोधित कर कर रहे थे तो उस दिन अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के संसद सदस्य संसद से अनुपस्थित थे, क्योंकि जब हम जनता के साथ मिलकर बाहर विरोध कर रहे हैं तो हम अपना विरोध हर जगह दर्ज करेंगे।

भारत की चारों वामदलों द्वारा 8 नवम्बर 2010 को राष्ट्रव्यापि संयुक्त विरोध प्रदर्शन में अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

अयोध्या का फैसला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लखनऊ बेंच द्वारा दिया गया निर्णय अंतत: सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिये भेज दिया। तीन सदस्यीय बेंच द्वारा दिया विशाल निर्णय, जिसके साथ एक असहमति पत्र भी था, जो कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये 18 वर्ष के कठिन परिक्षण के पश्चात् आया कि उसके तीनों दावेदारों को संतुष्ट नहीं किया जा सका। पार्टी का मत है कि माननीय न्यायालय के निर्णय ने मुकदमें के अनुकुल निर्णय न देकर इस मुकदमे को विभाजित करके मामले को संभाला है। निर्णय में भरोसे और विश्वास पर निर्णय लिया है जिसका दूरगामी परिणाम होने की उम्मीद है। अखिल

हिन्द फारवर्ड ब्लॉक को आशा है कि सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील विवादों पर यथार्थवादी दृष्टिकोण रखेगा और भविष्य में होने वाले अन्य सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिये निष्पक्ष फैसला देगा। कट्टरपंथी संगठनों के उत्तेजित वक्तव्यों में न बहकर भारत की जनता ने धर्मनिरपेक्षता की को मजबूत करते हुये एकता और विश्वास की जो मिसाल पेश की उसके लिये पार्टी देश की जनता को सलाम करती है। जब हमारे देश की व्यवस्था इन मुद्दों को नियोजित करने में विफल हो गयी तो देश की जनता ने धर्मनिरपेक्षता में विश्वास दिखाया तथा अपनी एकता का प्रदर्शन किया।

उच्च विकास दर के बावजूद, भूखमरी में बढ़ोतरी

यह बड़ा ही विरोधाभास है की भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी के प्रचार के साथ-साथ देश में भखों का भी सूचकांक तेजी से बढ़ रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत करने के साथ, अपने प्रथम लक्ष्य समावेशी विकास प्रति पूरी तरह से सुरमय हो गयी। लेकिन परिस्थिति अभी तक साफ नहीं हो पायी की विकास का परिमाप क्या है। जनता के समूहो में "आम आदमी" को लक्ष्य बनाकर सरकार ने अपने उत्तर को बड़े ही उत्साहीत ढंग से पेश किया। लेकिन कड़वा सच यह है कि देश का अमीर और अधिक अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की की कीमत का सूचकांक 17 प्रतिशत को भी पार कर गया और सामान्य कीमत का सूचकांक दो अंकों के पार जा चुका है। और जनता के जिस समूह को इस बढ़ती हुई कीमत ने प्रभावित किया है वह कोई और नहीं वहीं 'आम आदमी' है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है जिससे गरीब लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वे अपने जरूरत के अनुसार अनाज की मात्रा खरीद पाने में सक्षम नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि भूखे और कुपोषितों की संख्या बढ़ती जा रही है।

इस प्रकार की खतरनाक स्थिति का उजागर हाल ही में इंटरनेशनल फूड पोलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑन द एनुअल ग्लोबल हंगर इण्डेक्स फॉर 2010 की प्रकाशित रिपोर्ट (दिनांक 11.20.2010) से हुआ, जिसके अनुसार 84 विकासशील देशों में भारत को दो पायदान नीचे खिसकाकर 67वां स्थान दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, सुडान, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया का स्थान भारत से अच्छा है। भारत का यह गीरता ग्राफ यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके पड़ोसी मुल्कों से भी काफी पीछे है जैसे श्रीलंका (32वां स्थान), पाकिस्तान (52वां), नेपाल (56वां) का स्थान है, जो गरीबी से जुझने में भारत से अच्छा कार्य कर रहे हैं। चीन 9वें स्थान पर है, ग्लोबल हंगर इण्डेक्स (जीएचआई) में छठवां स्थान है।

किसी देश का लोबल हंगर इण्डेक्स (जीएचआई) का पैमाना 100 अंकों तक दिया होता है; यदि किसी देश का अंक शून्य (0) है तो कोई भूखा नहीं है और यदि 100 है तो उस देश की स्थिति भयावह है। यह रैंकिंग तीन एक समान स्तरों पर मापा जाता है, पूरी आबादी में कुपोषण के शिकार की संख्या, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वजन, और कम वजन के कारण मृत्यु दर। भारत का आंकड़ा क्रमश: 22 प्रतिशत, 43.5 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि लोबल हंगर इण्डेक्स में भारत का अंक 24.1 है, जो कि खाद्य सुरक्षा की परिस्थिति के खतरनाक होने का संकेत देता है।

भारत की आर्थिक विकास रिपोर्ट की कहानी इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक है। भारत की आर्थि विकास दर 2009-10 में 7.4 प्रतिशत दिखाया गया और उम्मीद जताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8.5 हो जायेगी। साधारणता आर्थिक प्रगति और भूख का स्तर एक दूसरे के विपतिरत जाते है। जिन देशों का सकल राष्ट्रीय आय या जिनका ग्लोबल न्यूट्रिशन इण्डेक्स (जीएनआई) उच्च है उनका ग्लोबल हंगर इण्डेक्स का स्कोर कम होता है, ऐसा चीन का है, जिसका जीएनआई उच्च और जीएचआई (6.0) है। लेकिन कुछ देश इस तथ्य के अपवाद भी है, जैसे दुर्भाग्य से भारत, जिसका ग्लोबल न्यूट्रीशन इण्डेक्स ऊँचा है लेकिन ऐसे में इसका ग्लोबल हंगर इण्डेक्स (24.1) है।

इस प्रकार की परिस्थिति की व्याख्या करते हुये, अर्थशास्त्री इस बात पर हुये की भारत और चीन में भूखमरी का इण्डेक्स में कमी या बढ़ोतरी में काफी अंतर है और इसका कारण इनके विकास दर। भारत का विकास दर अधिकतर सेवा क्षेत्र की जुड़ी है विशेषकर टेलिविजन और टेलिकाम में। लेकिन यह अपने कृषि क्षेत्र को लगातार अनदेखा कर रहा है जहाँ वैज्ञानिक तरीके से नहीं है तथा पिछढ़ा हुआ है। दूसरी ओर, चीन अपनी अर्थव्यव्था को सफलतापूर्वक तेजी से बढ़ा रहा है, कृषि वैज्ञानिक तरीकें से होती है तथा जो उत्पादन और सेवा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है।

जहाँ तक भूखमरी की समस्या का संदर्भ है, यह बताया जा चुका है कि कृषि के क्षेत्र में 2-3 बार बढ़ोतरी ही भूखमरी कम कर सकता है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि हमें कृषि पर विश्वास करके आगे बढ़ना ही अच्छा रास्ता है जिससे भूखमरी की समस्या भी कम होगी।

लेकिन भारत कृषि क्षेत्र को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र में गरीब लोगों का निवेश, कृषि की वैज्ञानित पद्धति नहीं होना, कृषि के बढ़ावे के सभी कदमों को अनदेखा करना और लाखों गरीब किसानों का पलायन, कर्ज के बोझ और दु:ख से इनमें से कई को आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। भारत का कृषि विकास दर 2009-10 में चिंताजनक वित्तीय विकास 0.2 प्रतिशत था। भूख का उन्मूलन और आम आदमी के लिये भोजन की व्यवस्था की प्राथमिक आवश्यकता के कर्तव्य को सरकार भूला चुकी है। अब यह पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। जब तक यह सरकार अपने अमीरों और कारपोरेट परस्ती नहीं छोड़ेगी तब तक आम आदमी में बढ़ती भूखमरी कम नहीं होगी।

बढ़ती महँगाई

संसद में कई बहसों के बाद भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। त्यौहारों के मौसम में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू गई। लेकिन सरकार महँगाई के प्रति सांख्यिकी और आर्थिक आंकड़े पेश करके विकास को प्रदर्शित करने में लगी रही, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलने वाली। महँगाई रोकने के लिये सख्त मापदंड अपनाने की बजाय सरकार ने पेट्रोलियम कम्पनियों को विभिन्न धारणाओं के तहत तेल की कीमतें बढ़ाने की छूट दे दी। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक महँगाई के खिलाफ, सार्वजनिक वितरण के प्रति सरकार के बेरूखी रवैये के खिलाफ और आवश्यक वस्तुओं की वायदा कारोबार को रोकने के लिये लगातार जन आंदोलन करता रहेगा।

जम्मु और कश्मीर

कश्मीर घाटी में शान्ति स्थापना के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम की अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक स्वागत करता है। ऑल पार्टी मीटिंग और संसदीय प्रतिनिधि मंडल का कश्मीर दौरा ज्वलंत मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये अच्छा निर्णय था। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का मत है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को इन कदमों के साथ-साथ कश्मीरी जनता को विश्वास में लेने के लिये सभी कार्यक्रमों और नीतियों की घोषणा करनी चाहिये। ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिये आठ बिन्दुओं का कार्यक्रम और सभी मुद्दों पर वार्ताकारों की सरकार द्वारा नियुक्ति एक अच्छा निर्णय है। दोनों ही सरकारों को जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिये तथा घाटी में महत्त्वपूर्ण कदम उठाने चाहिये जैसे - रोजगार के अवसर, संरचनात्मक विकास, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज के तहत सत्ता का केन्द्रीयकरण, अतिरिक्त सेना की वापसी और 'सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) हटाना। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक का मत है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरी पार्टी का इसमें दखलअंदाजी न हो। इन मुद्दों का समाधान पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचित से ही हल किया जाये।

कॉमन वेल्थ गेम्स घोटाला : संयुक्त संसदीय कमिटी का गठन हो

नई दिल्ली में हाल ही संपन्न हुई कॉमन वेल्थ गेम्स की तैयारियों में भ्रष्टाचार के अभूतपूर्व श्रृंख्लाओं का उद्गम हुआ है। इससे यह पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों ही इस घोटाले में शामिल है। एक दागी सरकार के देख-रेख में जाँच-पड़ताल से मुख्य आरोपियों और अपराधों का खुलासा नहीं हो सकता। अत:, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक की मांग है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के सभी पहलूओं की जाँच व पूछताछ जल्दी से जल्दी व पूरी करने के लिये संयुक्त संसदीय कमिटी का गठन अवश्य होना चाहिये।

कॉमन वेल्थ गेम्स के उत्साहनजन प्रदर्शन की प्रकाश में और नई योग्यताओं को विकसित करने के कार्यक्रमों की अपेक्षा, सरकार व्यापक एवं वैज्ञानिक होने के साथ-साथ देश में पारदर्शी खेल नीति बनाये।

केन्द्रीय मंत्री ए. राजा को हटाया जाये

एक कण भी संदेह किये वगैर संचार मंत्री ए. राजा को हटा देना चाहिये। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में ए. राजा पूरी तरह शामिल है। एक मोटी गणना के अनुसार इस 2 जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले से राष्ट्रीय राजकोष को एक लाख करोड़ का घाटा हुआ है। सीबीआई जाँच के आदेश दे दिये गये है लेकिन भ्रष्ट मंत्री अभी भी गद्दी पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रश्न किया था कि "2009 में ही शिकायत दर्ज करायी गई, लेकिन मंत्री भी बने हुये है, क्या इसका यह अनुमान लगाया जाये कि सरकार इस तरह कार्य कर रही है। आप सभी को ऐसा करने कि आज्ञा दे रहे हैं ?" लेकिन प्रधानमंत्री ने शीर्ष न्यायालय के प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं दिया। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक यह मांग करता है कि केन्द्रीय मंत्रीमंडल से दागी मंत्री को हटाया जाये।

कर्नाटक की राजनीति : लोकतंत्र का मजाक

कर्नाटक में घटित हाल ही की राजनीतिक गतिविधियों से प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीत कर्नाटक सरकार देश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिये एक मजाक बन गयी है। धनी लोग दिन प्रति दिन सकार को नियंत्रित कर रहे हैं। भाजपा के बेल्लारी रेड्डी बंधुओं द्वारा विधायकों की खरीद-फरोख्त करके अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये कर्नाटक की जनता को चुनौती दे रहे हैं। खनिज पदार्थों का दोहन करने के लिये सरकार को परेशान कर रहे हैं। इन सबसे से लगता है कि राज्य की अन्य दागी पार्टियों जैसे कांग्रेस (आई) व जनता दल (सेकुलन) और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक को विश्वास है कि लोकतांत्रिक जनता इन भ्रष्ट राजनीतिक दलों को पाठ जरूर पढ़ायेगी।

मजदूरों एकता जरूरी

विकास के नाम पर भारत सरकार लगातार मजदूर विरोधी अपनाती जा रही है। मजदूरों की मेहनत की कमाई ईपीएफ (इम्प्लाईज प्रोविडेंट फण्ड) को शेयर मार्केट में हस्तांतरण करके कारपोरेट घरानों के हाथों में सौंप देने से मजदूरों के सामने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। राष्ट्रीय सम्पत्ति और सार्वजनिक उपक्रमों का अंधाधुँध तरीके से निजीकरण हो रहा है। सभी क्षेत्रों में ठेकेदारी व्यवस्था बना दी गयी। लेबर लॉ (मजदूर कानून) का सभी प्रतिष्ठानों में उल्लंघन हो रहा है। उचित कानून और नियमों की कमी के कारण अदालत भी प्रबंधन के पक्ष में निर्णय दे रहा है। कुछ आवश्यक कानूनों के पारित होने के बाद भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर सामाजिक सुरक्षा की लाभ लेने से वंचित है। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सभी कामगार मजदूरों से अर्ज करती है कि वे आगे आयें और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठायें। टी.यू.सी.सी. की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह असंगठित मजदूरों को उनके मुलभूत अधिकार दिलाने के लिये विशेष कदम उठाये और मजदूरों का संयुक्त आंदोलन तैयार करे।

युवा - छात्र मुद्दें

एक सर्वेक्षण के अनुसार 54 प्रतिशत भारतीय 25 वर्ष से कम उम्र के है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी सत्तारूढ़ दल इस महत्त्वपूर्ण वर्ग की अनदेखी कर रहा है या इसे सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। देश में मौजूद किसी भी प्रकार के अधिकार को पाने के लिये कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं है। देश में व्यापक राष्ट्रीय युवा नीति की बहुत बड़ी कमी है। डिसिजन मेकिंग प्रोसेस (निर्णय लेने कि प्रक्रिया) में युवा अपनी भागीदारी निभाने से वंचित है।

आज देश की शिक्षा नीति ऐसी बना दी गयी कि पेशेवर व उच्च शिक्षा सिर्फ अमीर और धनवान ही प्राप्त कर सकते है। प्रतिभा की कोई भूमिका नहीं है, जबकि के.जी. से लेकर पी.जी. स्तर तक शिक्षा में सिर्फ पैसे की ही वस्तु बनकर रह गयी है व्यवसायिकरण, निजीकरण, शिक्षा की कालाबाजारी

धड़ल्ले से जारी है। डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी पेशेवर संस्थान अनियंत्रित रूप से कुकुरमुत्ते की तरह फैलती जा रही है। इनमें से कई संस्थानों के प्रमाणपत्र किसी भी शिक्षा बोर्ड से स्वीकृत नहीं है। छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इन सभी युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ युवाओं और छात्रों को एकजुट होना होगा। ऑल इण्डिया यूथ लीग (ए.आई.वाई.एल.) और ऑल इण्डिया स्टुडेण्ट्स ब्लॉक (ए.आई.एस.बी.) को विशेष कार्यक्रमों के तहत युवाओं और छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने होंगे।

महिला सशक्तिकरण

महिला आरक्षण विधेयक संसद में अभी तक लंबित है। लोकसभा में अभी तक इसे स्वीकृति नहीं मिली। कई राज्यों में पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित कर चुकी है। यह बड़ी ही चिंता का विषय है कि महिला सशक्तिकरण के लिये उठाये गये इस प्रकार के निर्णयों के बावजूद भी, महिलाओं पर अत्याचार जारी है। सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका ही इन पर होने वाले अत्याचारों को रोक सकती है। महिलाओं को उनके उचित, लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति (ए.आई.ए. एम.एस.) विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा।

केरल के स्थानीय निकाय चुनाव

केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 23 से 25 अक्तूबर 2010 तक हुये। कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने सत्तारूढ़ सीपीएम नीत सत्तारूढ़ वाम मोर्चे पर बढ़त हासिल की। 2005 के चुनाव में, वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को नगर निगम, नगर पालिका, जिला और ग्राम पंचायत में 49 प्रतिशत मत प्राप्त हुये थे। लेकिन इस बार उन्हें कई सीटें गंवाई और उन्हें मात्र 42 प्रतिशत मत प्राप्त हुये। और वहीं संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने अपनी मत प्रतिशतता को बढ़ाकर कर 46 प्रतिशत वोट प्राप्त किये। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे का इस प्रकार 7 प्रतिशत वोट का खोना यह संकेत करता है कि प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् मामूली से एक या दो प्रतिशत अंतर से हार से सत्ता परिवर्तन की प्रवृत्ति जारी रहेगी। चुनावी नतीजें दर्शाते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय वाम लोकतांत्रिक मोर्चा विरोधी रूझान जारी है।

अल्पसंख्यक समुदाय ने अपने वोट संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे को दिये। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के कुछ नेताओं द्वारा ईसाई और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ वक्तव्य देने से अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ नाराजगी थी। संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने इस परिस्थिति में संभल-संभलकर कदम आगे बढ़ाया और सांप्रदायिक ध्रवीकरण को अपने पक्ष किया। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने अपने कई पुराने पंचायतें, नगर निगमों और निकाय क्षेत्रों को खो दिया, जिसका अर्थ है कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने अपनी ग्रामीण व शहरी कई क्षेत्रों खो दिया। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार की कार्यशाली चुनावी मुद्दा नहीं थी बल्कि नेताओं ने अपना ध्यान अन्य मुद्दों जैसे विश्वास, धार्मिक मुखियाओं का राजनीतिक हस्तक्षेप, लाटरी घोटाला आदि रहे, जो कि स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे नहीं थे। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को एकजुटता के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ पुन: प्राप्त करनी होगी।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक ने 133 सीटों पर चुनाव में भाग लिया। यह पहला अवसर था जब फारवर्ड ब्लॉक ने केरल में इतने बड़े स्तर पर स्थानीय निकाय चुनाव में भागीदारी की। हमने किसी सीट पर जीत दर्ज नहीं कि लेकिन हम पंचायत वार्डों पर दूसरे नंबर पर रहे। अन्य सीटों जैसे जिला, ब्लॉक, पंचायत और नगरपालिका पर हमें अच्छे वोट प्राप्त हुये। चुनाव के दौरान पार्टी को बहुत ही अच्छा प्रचार मिला। चुनाव में हिस्सा लेने से, पार्टी केरल की राजनीति की मुख्यधारा में आ गई।

बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार विधान सभा चुनाव का चुनाव 24 नवम्बर 2010 को परिणाम आने के साथ समाप्त हो गया। जिसमें सत्तारूढ़ जनता दल (यू) - भाजपा गठबंधन, कांग्रेस (आई) और आरजेडी-एलजेपी गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किये। दुर्भाग्य से वाम एकता मोर्चे का गठन चुनाव पूर्व नहीं हो पाया। अत:, सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई (एमएल) ने एक साथ कई सीटों पर चुनाव लड़ा। फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी ने अलग-अलग चुनाव में भागीदारी की। सीपीआई (एमएल) के बड़ी भूमिका और अन्य दो वाम दलों ने वाम एकता के संदेश का प्रचार राज्य में नहीं किया। भविष्य में वाम एकता का राज्य में प्रचार करना अच्छा साबित हो सकता है, यदि सभी वाम दल एक साथ संयुक्त होकर राज्य में चुनाव लड़े। यह सत्य है कि वाम मोर्चे का विभाजन दक्षिण पंथियों को फायदा पहुँचाता है। जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा।

भूमि अधिग्रहण कानून का नवीनीकरण जल्दी होना अनिवार्य।

- भूमि गंवाने वालों का पुनर्वास व उचित मुआवजे का व्यापक पैकेज दिया जाये।
- उद्योग व सुविधाओं सहित जनहित और विकास कार्यों के साथ राज्य सरकार के साथ-साथ उद्यमि/बाजारी शक्तियाँ भूमि मालिकों से सीधे जमीन प्राप्त कर सकती है।

खाद्य सुरक्षा कानून तुरंत पारित किया जाये।

- शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और कम आय वाले (एपीएल) वालों के लिये।
- सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य अनाजों के साथ-साथ आवश्यक वस्तु उपलब्ध हो।
- कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की जाये।

रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट पेश की जाये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक सरकार से आग्रह करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर रंगनाथ मिश्र कमिशन की रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद

सत्र में प्रस्तुत करें।

भारत के मजदूर आन्दोलन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की शानदान भूमिका

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्वतंत्रता आन्दोलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी व्यक्तित्व एवं भूमिका रही है। उनका मानना था कि मजदूर वर्ग के बिना भागीदारी केक तथा ट्रेड यूनियन आन्दोलन को बिना तेज किये स्वतंत्रता आन्दोलन को मजबूत नहीं किया जा सकता है। इसलिए नेताजी देश के कामगार वर्गों की समस्याओ को प्रमुखता से उठाया एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। औद्योगिक मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए अपने राजनीतिक गरू देशबन्धु चित्तरंजन दास से प्रेरित होकर 1924 से नेताजी कलकत्ता के निकट मेयर चित्तरंजन दास अधीन निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में योदान दिए एवं गरीब मजदूरों के कलयाण के लिए उन्होंने बहुत से उल्लेखनीय कार्य किये। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल, साफ-सफाई का बेहतर कार्य किया। लेकिन अँग्रेजों ने नेताजी को गोपनीय क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में अक्तूबर 1924 को पहली बार गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद वे ग्यार बार जेल में बंद किये गये। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 1928 से ट्रेड यूनियन आन्दोलन के प्रमुख रूप से जुड़ गये एवं वे 1929 में ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के अध्यक्ष निर्वाचित किये गये। 16 सितम्बर 1929 को अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे देश की वामपंथी का उदय ट्रेड यूनियन आन्दोलन से हुआ है और वर्तमान वामपंथ की शक्ति एवं महत्त्व बढ़ा रहा है। 23 जनवरी 1930 के अपने वक्तव्य में नेताजी सुभाष ने कहा कि सरकारी दमन का पहिया तेजी से घुम रहा है इसलिए कामगार वर्ग के आन्दोलन को इसका मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली बनना होगा। मैं भारतवर्ष के कामगार वर्ग को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन (एटक) का अध्यक्ष चुना है। नेताजी ने केवल ब्रिटिश पूँजिपति ही नहीं बल्कि भारतीय पूँजिपतियों जो मजदूरों का शोषण किया करते थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक में प्रस्ताव पेस किया कि भारतीय पूँजीपतियों एवं विदेशी पूँजीपतियों ने बिना भेदभाव के मजदूरों के शोषण के खिलाफ मजदूर आन्दोलन को बढ़ाया जाना चाहिये। 1928 में साइमन कमिशन के कलकत्ता भ्रमण के द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अगुवायी में बंगाल प्रांतीय कमिटी में मजदूर वर्ग को संगठित कर कमिशन के विरोध स्वरूप हड़ताल का आयोजन करा दिया जिसके कारण ब्रिटिश अधिग्रहित कलकत्ता ट्रामवे कंपनी ने शामिल होने के आरोप में अपने चार कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया एवं अनेक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इसके विरोध में सुभाष ने फरवरी 1928 में एक आम सभा के अध्यक्षता करते हुए राज्य के लोगों दण्डित कर्मचारियों के पक्ष में खड़ा होने एवं उनको आर्थिक रूप से मदद करने का आह्वान किया। इस प्रकार बंगाल, बिहार सहित देश के मूजदूर आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने लगे। नेताजी साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गये। 4 जुलाई 1931 को कलकत्ता में ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन (एटक) के सत्र में हम नेताजी सुभाष के ऐतिहासिक अध्यक्षीय भाषण को याद कर सकते है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मजदूर काम का अधिकार चाहते है। सरकार का दायित्व है कि वह मजदूरों को रोजगार दे और यदि सरकार रोजगार देने में विफ रहती है तो वह अपनी जवाबदेही को स्वीकार करें। मजदूरों को नियोक्ता की कृपा पर भूखों मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। मनमाने ढंग से मजदूरों को बर्खास्त किये जाने से औद्योगिक अशांति बढ़ेगी। बिहार के मजदूरों ने नेताजी से उनके आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। नेताजी परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से खड़गपुर एवं लिलुआ के रेल कर्मियों, बोरियों, जुटमिल के कामगारों एवं बर्मा आयल कम्पनी के मजदूरों के आन्दोलन एवं हड़ताल में भाग लिया एवं उनका नेतृत्व किया था।

मजदूरों के लोकप्रिय नेता नेताजी सुभाष 1928 में तत्कालीन उद्योग जगत के भीष्म पितामह जमशेद जी नसरवान जी टाटा की टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी एवं टिन प्लेट कम्पनी के कामगारों को आंदोलन एवं हड़ताल का समर्थन एवं नेतृत्व करने के लिए जमशेदपुर आये और इस प्रकार उन्होंने भारीय मजदूर आन्दोलन के इतिहास में अपनी शानदान जग बनाई।

नेताजी ने रेल कर्मचारियों के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 5 मार्च 1928 में लिलुआ रेलवे वर्कशॉप के लिए 14000 रेल कर्मचारियों के आन्दोलन के साथ नेताजी नजदीक से जुड़े हुए थे। 25 मार्च को जब ये कामगार अपने बर्खास्त कर्मियों की सेवा वापसी की मांग करने के लिए ईस्ट इण्डिया रेलवे की फेयर ली प्लेस कलकत्ता मुख्यालय में रैली लेकर जा रहे थे, उसी समय पुलिस ने गोली चलाई जिसमें दो व्यक्ति मारे गये व कई घायल हो गये।

10 अप्रैल 1928 को खड़गपुर में बंगाल, नागपुर रेलवे के कर्मियों के आन्दोलन में नेताजी ने अपना समर्थन एवं नेतृत्व दिया।

16 अगस्त 1929 को लिलूआ में रेल कर्मियों की विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं है। रेलवे की आमदनी बढ़ रही है लेकिन रेल कर्मियों की हालत खराब है। उन्होंने कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मजदूर आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। बजबज आयल एण्ड पेट्रोल कम्पनी कोलकाता के छः माह से जारी 6000 कर्मचारियों के हड़ताल पर 27 अक्तूबर 1929 की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रबंधन की हठधर्मिता की कड़ी आलोचना की। नेताजी उस यूनियन के अध्यक्ष चुने गये उन्होंने इसका नेतृत्व किया। उस

समय की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सुभाष चन्द्र बोस एवं उनकी पार्टी देश के स्टेशन, बंदरगाह, जल परिवहन, ट्रामवे रोड़, ट्रांसपोर्ट, जुटमिल और अन्य बड़ी कम्पनियों के कर्मचारियों के बीच 1928-29 में काफी प्रभाव था। सुभाष पुलिस आदेश की अवहेलना कर कलकत्ता के समीप गोलघर जगदल के जुटमिल कर्मियों की सभा को संबोधित किये। उन्हें स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर 31 घंटे पुलिस अभिरक्षा के बाद 11 अक्तूबर 1931 को रिहा किया। झारखण्ड बिहार के कामगार के आन्दोलन में नेताजी का ऐतिहासिक योगदान रहा है। उन्होंने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी एवं टिन प्लेट कम्पनी के कर्मियों के आन्दोलन का नेतृत्व किया। टिस्कों के कर्मियों ने जब हड़ताल किया तब 19 अगस्त 1928 को नेताजी सुभाष जमशेदपुर आये। उनके साथ बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य समसुद्दीन भी थे। 1928-29 में झारखण्ड के कोयला खनन क्षेत्रों के मजदूरों के आन्दोलन में नेताजी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

1938 में नेताजी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे। 1939 में दूबारा महात्मा गाँधी के विरोध के बाद भी नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। 1938-39 के दिनों नेताजी ने झारखण्ड के धनबाद इलाके में झरिया, जामाधोबा, जोरापोखर कोलियरी में कामगारों को संगठित कर उन्हें आजादी की लड़ाई की मुख्यधारा में जोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभायी। उन्होंने अनेकों बार कोयला कामगारों की सभाओं को संबोधित किया। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तिफा देने के बाद नेताजी ने एक वर्ष देश भर की करीब एक हजार आम सभाओं को संबोधित किया एवं छात्र नौजवान मजदूर किसान एवं मेहनत कस आवाम को देश की आजादी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आवाह्न किया। नेताजी सुभाष 1929 में ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के अध्यक्ष चुने गये, विवाद होने से बी.टी. रमनदीवे ने अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव लाये जो मतदान के दौरान 26-24 से पराजित हो गये। इस विवाद के कारण के देश का ट्रेड यूनियन कमजोर हुआ।

पुन: 13 फरवरी 1939 को कलकत्ता ट्रामवे कर्मियों के 45 कर्मियों को हटाये जाने के खिलाफ उठे आन्दोलन से नेताजी सुभाष ने भरपुर समर्थन किया एवं मजदूरों के पक्ष में आगे आये। 1938-39 के दौरान अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के संस्थापक अध्यक्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस झारखण्ड के धनबाद, झरिया, जामादोवा, जोरीपोखर, जियलजोरा कोरियरी के कामगारों को संगठित कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा शामिल कराने के लिए ऐतिहासिक योगदान किया। मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय हित एकजुटता को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित महान मई दिवस पर कलकत्ता के श्रद्धानंद पार्क में 1 मई 1940 को आम सभा की अध्यक्षता किया। 11 जनवरी 1938 को लंदन के सेट पैंक्रास हाल में प्रख्यात मजदूर नेता रजनीपाम दत्त की अध्यक्षता में आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने स्पष्ट रूप से कि भारत के भविष्य के साथ दुनिया के सभी गुलाम व्यक्ति के भविष्य के साथ जुड़ा है। इसलिए मुझे पूरा वियवास है कि भारत की आजादी का मतलब मानवता की रक्षा। फरवरी 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में नेताजी ने कहा कि कांग्रेस कर्मियों को भारी संख्या में देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन सहभागित करनी चाहिए।

(साथी जनार्दन पाण्डेय, अध्यक्ष अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक, झारखण्ड प्रांतीय कमिटी)

पिछले अंक का शेष.......

आजाद हिन्द फौज – संयुक्त भारत के लिये संयुक्त संघर्ष

(डॉ. श्रीमती अजीत जावेद, एसोसिएट प्रोफेसर, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

टंक रोड़ सिंगापुर स्थित छेतियार मंदिर के संचालक को सहयोग (राशि) देने के लिये बोस ने पत्र लिखा, उत्तर में संचालक गणों ने सहयोग देने के लिये हाँ भरा परन्तु बोस को मन्दिर पर आकर भाषण देने के लिये भी आमंत्रित किया। नेताजी मंदिर पर जाकर भाषण देना उचित नहीं समझा क्योंकि वे राज्य के मामलों को धर्म के साथ मिलाना नहीं चाहते थे। फिर भी मंदिर के संचालकगण अनुरोध करते रहे। उनके लगातार अनुरोध पर नेताजी इस शर्त पर तैयार हुये कि उनके साथ जात-धर्म से उठकर हर तरह के अधिकारी साथ होंगे। संचालकगणों ने नेताजी अनुरोध को स्वीकार कर लिया। नेताजी अपने साथ मुसलमान, सिख और ईसाई अधिकारियों के साथ वहाँ गये। वे मंदिर के परिसर में गये और बंद दरवाजे करके पवित्र अंदर के भाग में भी गये जहाँ ब्राह्मण ही जाने के अधिकारी होते है। ब्राह्मण पुजारी ने उन सभी अधिकारियों के ललाट पर तिलक लगाया बोस का नेतृत्व ही कुछ ऐसा था जो उनके साथियों में ऊँचे भाव भर देता था। ईद के अवसर पर सभी हिन्दु अधिकारी मस्जिद गये और उस अवसर पर खतम दावा सबने सुना। ए.सी. चटर्जी के अनुसार, जो अवसर पर उपस्थित थे, ने बताया कि उन सभी लोगों ने उक्त अवसर पर भाग लिया और निर्मित खाद्य वस्तुओं का आनंद उठाया। ऐसा ही दृश्य दिवाली के दिन मुस्लिम अधिकारियों के साथ घटित हुआ। इसी तरह हिन्दु और मुसलमान अधिकारी अपने साथ सिख अधिकारियों के साथ गुरूद्वारे जाते थे........ । इस तरह धीरे-धीरे सबके अन्दर एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, प्रेम और आदर का भाव भरने लगा।

आजाद हिन्द फौज के हर सदस्य के भीतर भारतीय होने का यह पवित्र भाव सुभाष के धर्मनिरपेक्ष दृष्टि, स्वार्थहीन देशभक्ति और प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण भर उठा। कहीं किसी तरह का सांप्रदायिक या अलगाववादी भाव वहाँ नहीं था। फौज में मुसलमानों की भारी संख्या थी। वहाँ सभी के लिये एक ही रसोई घर था और भाई चारा का माहौल था।

भारत की मुक्ति की योजना का कार्यक्रम बन चुका था और उसके अनुसार अस्थायी सरकार का मुख्यालय जनवरी 1944 को रंगून में स्थानांतरित हो

चुका था। आजाद हिन्द बैंक खुल चुका था। सबसे पहले शाह नवाज के नेतृत्व में 3000 सैनिकों का सुभाष ब्रिगेड युद्ध के मैदान में भाग लेने बर्मा पहुँच चुका था। **सैनिकों में प्रथम टुकड़ी में शामिल होने का उत्साह बहुत अधिक था। डॉक्टर के द्वारा बिमार होने या शारिरिक रूप से अक्षम सैनिकों ने टुकड़ी में न शामिल होने की बात सुनकर रेलवे स्टेशन पर चले गये और रेलवे इंजन के सामने लेट गये कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सीमा पर लड़ने के लिये भेज देने का आदेश नहीं पायेंगे।**

मार्च 1944 के मध्य में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों ने अत्यंत प्रशंसित अफ्रिका की निग्रो टुकड़ी, जो ब्रिटिश सेना का भाग थी और कालदान नदी के ऊपर पुल व्यस्त थी, को हराया था। आजाद हिन्द फौज की टुकड़ी जापानी सैनिक बलों के द्वारा शक्ति समर्थित थी और भारतीय सीमा की तरफ आजाद हिन्द फौज की टुकड़ी बढ़ने लगी। आजाद हिन्द फौज दो मोर्चो पर, एक आराकण क्षेत्र और दूसरी तरफ इम्फाल रोड़ मोर्चे पर सक्रिय थी। भारतीय सीमा में सबसे नजदीक ब्रिटिश पोस्ट मोडोक में था, जिस पर मई 1944 में कब्जा कर लिया गया। भारतीय क्षेत्र में आजाद हिन्द फौज का प्रवेश हृदय का छूने वाली घटना थी। सैनिकों ने साष्टांग लेटकर भारतीय भूमि का नमन किया और पवित्र मातृभूमि की धरती को भावनाओं के ज्वार में बहकर चुबन किया जिसकी मुक्ति के लिये अब वे आगे बढ़ चुके थे। नियमित रूप से झण्डारोहण बहुत ही उत्साह के बीच हुआ और आजाद हिन्द फौज का राष्ट्रीय गान गाया गया।

बोस के प्रेरणादायि नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज कोहिमा की बढ़ी साथ में जापानी सैनिक भी थे और मार्च 1944 में कोहिमा पर कब्जा हो गया। परन्तु मई के अंत में एलिड फोर्स उत्तर के लिये अच्छी तरह तैयार थी। आजाद हिन्द फौज के सैनिक कोहिमा में पोस्ट (प्रहरी स्थान) की रक्षा के लिये जोरदार संघर्ष किया और ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। यहाँ तक कहा जाता है कि आजाद हिन्द फौज के सैनिक अपनी पीठ पर विस्फोट बम बाँधकर ब्रिटिश टैंकों के सामने विस्फोट करने के उद्देश्य से अपने शरीर को उछाल कर फेंकते थे। इस प्रकार के जांबाज संघर्ष में आजाद हिन्द के लगभग 4000 सैनिक शहीद हुये। मूसलाधार बारिश ने रसद की सप्लाई को बाधित किया। ब्रिटिश बर्मा की तरफ बढ़ गयी जापानी सेना पीछे हट गयी। रंगून जो आजाद हिन्द फौज के हाथों में था, उसे मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया। झांसी की रानी टुकड़ी की बहादुर नारियां पुरूषों के साथ इस युद्ध में लड़ी और बराबर की संख्या में शहीद हुई। जब सेना पीछे हटने को बाध्य हुई तो महिलाओं के साथ पुरूष ने 1000 किलोमीटर से अधिक का परेड किया। यूरोप में इटली घुटने टेक चुका था, जर्मनी ढह रहा था, आजाद हिन्द फौज के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनके हथियार छीन लिये गये और कैदी बनाकर भारत ले आये।

आजाद हिन्द फौज के प्रमुख बोस को संघर्ष की अभी भी उम्मीदें थी। जुलाई के प्रारंभ में वे बर्मा से सिंगापुर चले आये जहाँ आजाद हिन्द फौज स्मारक की स्थापना की जिसके ऊपर शब्द खुदवाये गये :'इत्तेफाक (एकता), ऐतमाद (आस्था) और कुर्बानी (बलिदान)। बाद में इस स्मारक स्थल को माउण्ट बेटन के आदेश से एलिड फोर्सेस, जिन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया था, ने नष्ट कर दिया। अपने दोनों शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद ने जापान ने आत्म समर्पण कर दिया। बोस ने रूस जाने का कार्यक्रम बनाया। उनका कार्यक्रम संपन्न भी नहीं हुआ था और एक हवाई दुर्घटना में उनके निधन की बाते सामने आई (1941 में जब अंग्रेजों ने जाना कि बोस ऐक्सिस शक्तियों से सहयोग चाहते है, उन्होंने अपने एजेंटों को बोस के पीछे लग जाने का आदेश दिया और उनके जर्मनी पहुँचने के पहले ही उन्हें मार देने का आदेश दिया। एक ऐलिड समाचार एजेंसी के द्वारा मार्च 1942 में ही एक वायुयान दुर्घटना में सुभाष चन्द्र बोस के मारे जाने की घटना प्रकाशित हुई थी)। नीरज चौधरी के अनुसार।

गाँधीवादी कांग्रेसी के लिये सुभाष चन्द्र बोस ने मृत्यु के द्वारा हवा बहाई। अगर वे जीवित होते और भारत वापस आ गये होते तो पूरे देश में अपने पक्ष में आम जनता को वे बहा ले गये होते और उनके साथ अपनी पहचान न बनाये रखने के कारण कांग्रेस के लिये यह समय आत्मघाती होता और उनके पास जाना उनके लिये बहुत ही कठिन होता। उन्होंने गाँधी और नेहरू के नेतृत्व के लिये बहुत छोटा रोल छोड़ा होता और अपने शर्तों पर वे आगे बढ़ते।

बोस के निधन से भारत की आजादी के लिये आजाद हिन्द फौज का संघर्ष खत्म हो गया जबकि उनका बलिदान बेकार नहीं गया। जब आजाद हिन्द फौज के सैनिक कार्यवाही के लिये भारत लाये गये, पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने पहले कभी कहा था यदि बोस आजाद हिन्द फौज के साथ भारत आते है तो वे खुद हाथों में तलवार लेकर बोस से संघर्ष के लिये खड़े हो जायेंगे, और यही नहीं सिंगापुर की एक सार्वजनिक सभा में आजाद हिन्द फौज के स्मारक पर कोई श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किये थे, वही नेहरू अपने प्रतिद्वंद्विबोस के निधन के बाद जनता की भावना को भांप गये और अपना रवैया गिरगिट की तरफ बदल डाला उन्होंने आजाद हिन्द फौज की भूमिका का महिमा मंडल किया। नेहरू ने आजाद हिन्द फौज के पूरे कैडरों को चुनाव में लेफ्टिनेंट की तरह साथ लेकर चल पड़े। उन्होंने बोस के नारे दिल्ली चलो और जय हिन्द को अपना लिया। वोट की राजनीति में सार्वजनिक सभाओं में कांग्रेस के सभापति के कुर्सी पर विराजमान सुभाष बोस की फोटो जिसमें भारी मात्रा में मालायें पहनाई गयी थी, (इसी पद से निर्ममता पूर्वक कभी उन्हें हटाया गया था तथा कांग्रेस से निलंबित भी किया गया था) को लेकर घूमने लगे और सभायें करने लगे। आजाद हिन्द फौज के सैनिकों की सुनवाई के विषय पर पूरा देश उठ खड़ा हुआ, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सेना भी उनके पक्ष में खड़ी हो गयी। उम्रदराज होते कांग्रेसी नेता जहाँ अपने हाथों से सत्ता का सुख फिसलते हुये देख रहे थे उन्हें एक अच्छा मौका आजाद हिन्द फौज के कारणों से मिला, भले ही सत्ता हस्तांतरण देश के बंटवारें की शर्त (कीमत) पर ही क्यों न हुआ। लार्ड माउण्ट बेटन की अनुशंसा पर नेहरू राजी हो गये जिसके अनुसार देश की आजादी की शर्त तभी मानी जायेगी जब भारतीय सेना में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को कोई स्थान नहीं दिया जायेगा (शामिल नहीं किया जायेगा)।

ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चारों ओर हड़ताल और हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला चल पड़ा, जिससे पूरे देश में एकता का प्रदर्शन होने लगा। बंगाल में

प्रदर्शनकारियों ने सैनिक लारियों को नष्ट कर डाला और जब कैप्टन अब्दुल रसीद को सात वर्षों की कठोर सजा सुनाई गयी तो ब्रिटेन का झण्डा (यूनियन जैक) को उतार फेंका। अँग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलायी, जिसमें 53 लोग मारे गये और 500 से अधिक लोग घायल हो गये। 20 नवम्बर 1945 को एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश भारतीय सरकार ने स्वीकार किया किः

ऐसा शायद ही कभी कोई मुद्दा उठा होगा जिसमें इतने अधिक भारतीय जुड़े होंगे उन्हें सहानुभूति के शब्द कहना ही सुरक्षित है ...... सहानुभूति का यह भाव सभी सांप्रदायिक बांधों को तोड़ के फैल चुका है

सांप्रदायिकता का विषाणु आजाद हिन्द फौज को जरा भी प्रभावित नहीं कर सका था। एक प्रसिद्ध पत्रकार बी. शिवाराव के अनुसार, जो लाल किले के कैदियों से मिले थे और बताया था कि उनमें हिन्दु या मुसलमान होने का रंज मात्र भाव भी नहीं था, उन्होंने आगे बताया था कि लालकिले में सुनवाई की प्रतिक्षा में बैठे लोगों में सबसे अधिक मुसलमान थे। सुभाष चन्द्र बोस ने हिन्दु, मुस्लिम और सिखों को एक झण्डे के तले भारत की आजादी के लिये एकजुट करने में सफलता पाने के साथ-साथ देश की एकता के लिये वह कर दिखाया था जिसे करने में असफल रही थी। आजाद हिन्द फौज के संघर्ष में यह सिद्ध कर दिखाया था कि भारत की आजादी के मतवालों में हिन्दुओं से किसी भी मायने में मुसलमान कम उत्साहित नहीं थे। यदि आजाद हिन्द फौज ने सफलता हासिल की होती या बोस जीवित रह गये होते तो शायद देश विभाजित न हुआ होता।

- साभार मैनस्ट्रीम (अँग्रेजी पत्रिका)

(हिन्दी अनुवाद - प्रभाशंकर मिश्र, राष्ट्रीय सह-संयोजक जन संग्राम मोर्चा (जन संगठन)

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम की त्रि-देशी सम्मेलन आगरा में त्रि-देशीय संसद सदस्य मंच का गठन

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम की त्रि-देशीय महिला संभाग का दो दिवसीय सम्मेलन आगरा में 2 और 3 नवम्बर को संपन्न हुआ। जिसमें तीन देशों और 10 राज्यों (जम्मु एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा) से लगभग 203 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमें 29 महिलायें शामिल थी।

पहले दिन का सम्मेलन 2 नवम्बर 2010 को माथुर वैश्य भवन, पंचकुईयाँ, आगरा, उत्तर प्रदेश मेमं आयोजित हुई तथा दूसरे दिन का सम्मेलन 3 नवम्बर 2010 को यूथ होस्टल, संजय प्लेस, एम.जी. रोड़, आगरा में आयोजित हुई। श्रीमती अफरोजा हक रियाना संयोजक, त्रिदेशीय महिला चेप्टर और श्री रामजी लाल सुमन (सांसद) आगराने सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम का झण्डा रोहण किया। सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम की त्रिदेशीय मंच के अध्यक्ष श्री देवब्रत बिश्वास ने की। सम्मेलन को श्री रामजी लाल सुमन, श्रीमती अफरोजा हक रियाना, प्रो रामगोपाल वर्मा (सांसद), श्री देवब्रत बिश्वास, श्री सत्यपाल, डॉ. सूनीलम, प्रो. दलेल सिंह, श्री फयाज अहमद भट्ट, श्रीमती नूरजहाँ सिद्दिक्की, श्रीमती शहजादी सिमोन, श्रीमती जमशीदा गुल, श्रीमती सुमन जमवाल, श्रीमती जयन्ती साहु, श्रीमती लक्ष्मी मोहन्ती, श्रीमती पुर्णिमा पाण्डेय, श्रीमती रेखा सिंह, डॉ. नसरीन बेगम, श्रीमती निलु राहामान, श्रीमती मुस्तरी बेगम, माबुब आलम, सिराजुल इस्लाम रोनी, शंकर तालुकदार, रिता चक्रवर्ती, एड. रामकिशोर आदि ने संबोधित किया।

बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के महासचिव श्री माणिक समाजदार ने सभी को धन्यवाद दिया।

सम्मेलन का संचालन श्रीमती गोपा मुखर्जी, संचालक - भारत चैप्टर, और आगरा सम्मेलन के संयोजक डॉ. सुनीलम ने किया। इन दो दिनों में 30 प्रतिनिधियों में चर्चा में भाग लिया। जनाब नजीर अहमद जी ने संजय प्लेस के होटल मरीना श्री दिलीप मित्तल ने चौधरी गार्डन, वैभव नगर (रेडियो स्टेशन के नजदीक) श्री रामजीलाल सुमन के निवास पर रात्रि भोजन किया।

प्रतिनिधियों के लिये 3 नवम्बर की शाम को चौधरी गार्डन में एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुप्रसिद्ध गजल गायक मोहम्मद इमरान खान और उनकी टीम आईएफटीए, विश्वविद्यालय की अध्यापक और छात्रों की टीम, ने इस फोरम के मिशन से संबंधित गजल प्रस्तुत किया।

त्रि-देशीय आगरा सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः

1. नेशनल असेम्बली और त्रि-देशीय संसद सदस्य फोरम का गठन किया गया जिसके संयोजक त्रि-देशीय फोरम के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री देवब्रत बिश्वास, सांसद श्री मोइनुद्दीन खान बादल, सांसद श्री रामजीलाल सुमन, सांसद प्रो. राम गोपाल यादव, सांसद जनाब हसन उल हक इनु, सांसद श्री बरूण मुखर्जी, पूर्व सांसद शेख रहमान और डॉक्टर सत्य पाल चयनित किये गये।
2. धार्मिक अल्पसंख्यकों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की त्रि-देशीय सम्मेलन का आयोजन अमृतसर में मई 2011 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की

जायेगी।

3. श्री शंकर तालुकदार त्रि-देशीय छात्र एवं युवाओं को एकत्रित करने के लिये इंचार्ज चयनित किये गये।

4. अगली त्रि-देशीय कमिटी की सभा 5 जनवरी को ढाका में आयोजित होगी।

5. जहाँ 21 फरवरी को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के समारोह के आयोजन का निरीक्षण होगा।

6. पाकिस्तान में सफलतापूर्वक मीटिंग आयोजित होने के बाद त्रि-देशीय कमिटी जम्मु और कश्मीर का दौरा करेगा।

7. बांग्लादेश से तीन महिला श्रीमती मुस्तरी बेगम, श्रीमती निलु रहमान और जिनत रेहाना मिना और पाकिस्ताना से श्रीमति सरी मासुद (डॉक्टर सत्य पाल द्वारा प्रस्तावित) को त्रि-देशीय कमिटी की महिला चैप्टर में रखा गया है।

सम्मेलन में यह चर्चा की गयी कि इस फोरम को जन आंदोलन में बदल दिया जाये, जहाँ वे अपनी इच्छा प्रकट कर सके और सरकार पर इन मानवीय प्रतिबंधों को तोड़ने का दबाव डाला जा सके और वीजा की समस्या को संसद में उठाया जाये।

अगरा सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव ग्रहण किये गये:

हमसभी प्रतिनिधि व अन्य भागीदार प्रतिनिधि चौथे बांग्लादेश-भारत-पाकिस्तान पिपुल्स फोरम के सम्मेलन जो कि 2 और 3 नवम्बर 2010 को ताजमहल और सुलह-कुल (सर्वगत सहिष्णुता) के शहर आगरा में आयोजित हुआ, पुन: पुष्टि करते है कि हम इन देशों के नागरिक इस साम्राज्यवादी के बढ़ावे के आगे दब्बु बनकर नहीं रहेंगे। हम स्वयं ही अपने एकता की पारंपरिक धारणा को आगे बढ़ाने के लिये एक दूसरे के विचारों, और प्यार भरे संदेशों को जन-जन तक पहुँचायेंगे। फोरम का दृढ़ विश्वास है कि यह एकता साम्राज्यवादी ताकतों को हराकर और घिनौने मनसूबों को समाप्त कर व बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर उकसावे की राजनीति और जनता के बीच क्षेत्रिय उन्माद को ध्वस्त कर देंगे और जनता में एकता बनायेंगे। हम एकता को बढ़ाने के लिये नागरिक - दर - नागरिक संबंधों को एक दूसरे के साथ भाईचारे की प्रतिनिधी और विचारों व साहित्यों के पारस्परिक आदान प्रदान से मजबूत करेंगे।

यह वास्तविकता है कि इन बनावटी सीमाओं जो हम पर पिछले 63 वर्ष से लादी गयी है, हम एक दूसरे से दिमागी रूप से काफी दूर हो गये है, क्योंकि हमें भ्रमित किया जाता है और गलत सूचनायें प्रदान की जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमेशा नुकसानदायक एक दूसरे के लिये नुकसान देह ही रहा और जिसका फायदा सत्तारूढ़ लोगों और साम्राज्यवादी ताकतों ने उठाया। अत: फोरम यह निर्णय लेता है कि तीनों देशों की जनता के मध्य विश्वास और एकता को बनायेगा और साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को आगे बढ़ायेगा। यह केवल उप-महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह संदेश देगा।

साम्राज्यवाद का खात्मा का अर्थ - मानवता का बचाव है।

हमारा लक्ष्य होगा:

- बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच आपसी संबंध मजबूत करना।
- देशभक्तिपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जन आंदोलन करना।
- सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्धपूर्ण से समाधान।
- स्वतंत्रता संग्राम के असली संघर्ष को उजागर करना।
- साम्राज्यवाद विरोधी झण्डे को ऊपर उठाये रखना।

राष्ट्रीय महिला चैप्टर में निम्न सदस्या चयनित की गयी:

श्रीमती नूरजहाँ सिद्दिकी (हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश), श्रीमती शहजादी सिमोन (जम्मु और कश्मीर), श्रीमती जमशीदा गुल (जम्मु और कश्मीर), श्रीमती सुमन जमवाल (जम्मु और कश्मीर), श्रीमती जयन्ती साहु (उड़ीसा), श्रीमती लक्ष्मी मोहन्ती (उड़ीसा), श्रीमती छबी (कानपुर, उत्तर प्रदेश), श्रीमती पुर्णिमा पाण्डेय (उन्नाव, उत्तर प्रदेश), श्रीमती रेखा सिंह (झारखण्ड) श्रीमती जसविंदर कौर (पंजाब)।

केरल राज्य ऑल इण्डिया यूथ लीग सम्मेलन

ऑल इण्डिया यूथ लीग की केरल राज्य कमिटी का सम्मेलन पट्टनमथिट्टा टाउन हॉल में 25 व 26 सितम्बर 2010 को संपन्न हुआ। शहर को नेताजी, भगत सिंह और ऑल इण्डिया यूथ लीग के बैनरों से दुलहन की तरह सजाया गया था। सम्मेलन के पहले दिन आकर्षक युवा रैली निकाली गयी जिसमें सैकड़ों युवाओं ने विभिन्न जिलों से आकर शामिल हुये।

अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी एन. वेलप्पन नायर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने युवाओं से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह के आदर्शों व क्रांतिकारी मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भारत को आज नौजवान नेताओं की आवश्यकता है। ऑल इण्डिया यूथ लीग की अपनी एक विरासत और उसका कार्य है कि वह युवाओं को नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिये प्रेरित करे।

साथी सुब्बुराज कादीरवन (तमिलनाडु), राष्ट्रीय सचिव यूथ लीग केन्द्रीय कमिटी की ओर से पर्यवेक्षक थे। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये साथी सुब्बुराज ने राज्य में ऑल इण्डिया यूथ लीग की प्रगति पर अपना संतोष व्यक्त किया।

सम्मेलन में 12 जिलों से 165 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्ष मंडली में साथी एड. अरूण सासी, साथी एड. दिपिन थेक्केपुरम,

और साथी जी. राधाकृष्णनन थे। सम्मेलन के मुख्य वक्ता अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव साथी जी. देवराजन थे। इसके अलावा सम्मेलन को साथी नदाकुझीया जनार्दन नायर, साथी थाम्पी पुन्नाथालिया, साथी श्री कुमारी अम्मा, साथी डेनी पल्लीपट, साथी रिक्सोन, साथी अरून, साथी राजीव आदि ने संबोधित किया।

सम्मेलन में ऑल इण्डिया यूथ लीग की 31 सदस्यीय नई कमिटी का चयन किया गया। जिसमें अध्यक्ष – साथी एड. दिपिन थेक्केपुरम (त्रिसुर जिला), महासचिव – साथी के.वी. हरीन्द्रन (कन्नुर जिला) चयनित हुये।

दिल्ली राज्य महिला समिति का गठन

नई दिल्ली : दिनांक 14 नवम्बर 2010 को अखिल हिन्द अग्रगामी महिला समिति दिल्ली राज्य का गठन मंगोल पुरी, के–1200 में किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित पदिछाओं का चयन हुआ:

अध्यक्षा – साथी माया रानी गुप्ता, उपाध्यक्ष – साथी कल्पना झा, साथी मुकेश रानी, साथी रंजू देवी, साथी कमलेश शर्मा, साथी जी. प्रज्ञता, महासचिव – साथी राजलक्ष्मी देवी, वित्तसचिव – सविता देवी, सचिव – लक्ष्मी गुप्ता, राजकुमारी, रीना देवी, कीर्ती झा, कार्यकारिणी सदस्य – साथी मालती वर्मा, साथी सीता देवी, साथी विभा देवी, साथी रजनी देवी, साथी आशा देवी, साथी रिता देवी

टी.यू.सी.सी. के प्रांतीय सम्मेलन

दिल्ली : टीयूसीसी दिल्ली राज्य कमिटी छठवां राज्य सम्मेलन जवाहर लाल नेहरू यूथ सेन्टर, 219, दिनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में 31 अक्तूबर 2010 को संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता साथी कलावती सरन चिल्ड्रन अस्पताल इम्प्लाईज एसोसिएशन के महासचिव साथी शम्भुनाथ जायसवाल ने की।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि टी.यू.सी.सी. के राष्ट्रीय महामंत्री साथी एस.पी. तिवारी जी थे। सम्मेलन में विभिन्न मजदूर संगठनों से लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान टी.यू.सी.सी. की दिल्ली राज्य कमिटी का चयन हुआ जो पूरी तरह लोकतांत्रिक ढाँचे का पालन कर रही थी। जिसमें साथी शम्भूनाथ जायसवाल – अध्यक्ष, व साथी पी.एन. द्विवेदी – महासचिव चयनित किये गये इसके अलावा सचिव मण्डल में महिलाओं को स्थान देते हुये साथी लक्ष्मी देवी को सचिव पद पर चयनित करते हुये यह घोषणा की गयी कि राज्य कमिटी के सदस्यों का चयन अगली सभा में किया जायेगा।

केरल : टीयूसीसी केरल राज्य कमिटी का सम्मेलन 2 अक्तूबर 2010 को रेनबो ऑडिटोरियम, अलापुझा में आयोजित हुआ। अलापुझा जिला को नेताजी के बैनरों, उछलते शेर के झण्डे और टीयूसीसी के बैनरों से दुलहन की तरह सजा रखा था। अलापुझा जिला के लोगों के लिये यह एक अनोखा ही दृश्य था, जिसे देखकर वे सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। इससे पहले सम्मेलन की तैयारी के लिये पुरे राज्य में जोर–शोर से प्रचार–प्रसार किया गया। जिसे स्थानीय समाचार पत्रों, टीवी चैनलों आदि ने भी अच्छा कवरेज दिया।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि टीयूसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जी.आर. शिवशंकर जी थे। अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं टीयूसीसी के पूर्व के अध्यक्ष साथी एन. वेलप्पन नायर जी ने प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये साथी नायर जी ने कहा कि मजदूरों की रक्षा के आज संयुक्त आंदोलन के साथ–साथ लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ट्रेड यूनियन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल बड़े ट्रेड यूनियन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते क्योंकि उनसे उन्हें चंदा नहीं मिलता, अत: वे अपनी लड़ाई मात्र संगठित क्षेत्र के लिये करते है। लेकिन टीयूसीसी (ट्रेड यूनियन को–ऑर्डिनेशन सेन्टर) नेताजी के विचारों से ओत–प्रोत है जो पूरे राष्ट्रवादी सोच के साथ संगठित हो या असंगठित सभी के हित के लिये बराबर संघर्ष कर रही है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कोल्लम और उसके आस–पास के जिलों में काजू कामगार मजदूरों के प्रति शोषण के खिलाफ टीयूसीसी अपना संघर्ष कर रहा है।

मुख्य अतिथि साथी जी.आर. शिवशंकर ने टीयूसीसी के कार्यकलापों के प्रति संतुष्टी जाहीर करते हुये आज मजदूरों को एकत्रित करके

मजबूत मजदूर आंदोलन की आवश्यकता है। मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों को दबाने की प्रक्रिया केन्द्र व राज्य सरकारें दोनों ही कर रही है। वे देश में एक ही समीकरण पर कार्य कर रहे है वह है पूँजीवादी व्यवस्था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कानून को दांव पर रखकर कई–कई घंटे काम कराया जाता है। टीयूसीसी का केरल राज्य में एक अपना अलग ही महत्त्व है, क्योंकि यह राज्य में यूनियन संगठनों को नेताजी के विचारों से ओत–प्रोत होकर संगठित करता है। जिससे मजदूरों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है वे टीयूसीसी की ओर आकर्षित होते है।

इसके अलावा सम्मेलन के दौरान मजदूरों के अधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य वक्ता साथी जी. देवराजन जी थे।

सम्मेलन में विभिन्न यूनियन संगठनों से 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा एक नई 31 सदस्यीय केरल राज्य टीयूसीसी की कमिटी का गठन किया गया। जिसमें साथी के.आर. ब्रह्मानंदन (कोल्लम जिला) – अध्यक्ष व साथी ए.पी. अनिल कुमार (अलापुझा जिला) – महासचिव चयनित हुये।

मध्य प्रदेश : टीयूसीसी की मध्य प्रदेश राज्य इकाई सम्मेलन 18 सितम्बर को सतना में संपन्न हुई। जिसमें 8 जिलों से 92 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि टीयूसीसी के राष्ट्रीय महामंत्री साथी एस.पी. तिवारी जी थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में भारतीय इतिहास के पन्नों से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डाला और साथ ही यह भी कहा कि आज का मजदूर पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध को देखकर खुद को बौना मानकर चुप्पी साधे हुये है, उसने स्वयं पर विश्वास खो दिया और अपने विचारों को सिमित कर दिया कि पूँजीपति, बड़ी–बड़ी कम्पनियाँ और सरकारी अधिकारियों के आगे झुक कर ही रहना उनका जीवन है। यही विचार 1947 से देश के लोगों में वे यही मानकर चलते थे कि हम इस देश से अँग्रेजों को कभी भगा नहीं सकते और उनके साथ समझौता करके डोमिनियन स्टेटश पर चल रहे थे। लेकिन नेताजी सुभाष ये वह नाम है जिसने अनहोनी को होनी कर दिखाया और दिखाया की जब देश का मजदूर, देश का किसान, देश का युवा, देश का नौजवान एक हो जाये तो वह दुनिया के दौलतमंद और ताकतवर को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है। आज मजदूर भाईयों आप संगठित, असंगठित क्षेत्र में हो या कृषि मजदूर शोषण का शिकार तो सभी है अत: आज देश में संयुक्त संघर्ष की आवश्कता है।

इसके अलावा सम्मेलन में 25 सदस्यीय राज्य कमिटी का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष – साथी रामचन्द्र परमार, महासचिव – साथी संजय यादव, संयुक्त महासचिव – साथी अरूण प्रताप सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष – साथी राम अवतार पचौरी चयनित हुये।

राष्ट्रीय प्रगतिशील बीड़ी कामगार महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन

राष्ट्रीय प्रगतिशील बीड़ी कामगार महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन 11 नवम्बर को मध्य प्रदेश के दमोह में परिवार समस्या निवारण केन्द्र में संपन्न हुआ। जिसमें 3 राज्यों से कुल 84 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सम्मेलन की विशेषता यह रही कि इनमें लगभग 45 महिलायें थी। सम्मेलन के पश्चात् 17 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारीणी का गठन हुआ जिसके महामंत्री साथी हंसराज अकेला जी चयनि हुये।